

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

बनाम

अरुणाचल प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

9 जनवरी, 1996

[ए. एम. अहमदी, मुख्यन्यायाधिपति और एस. सी. सेन, न्यायाधिपति.]

भारत का संविधान:

अनुच्छेद 21-अरुणाचल प्रदेश में बसे चकमा-स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए उत्पीड़न-अभिनिर्धारित किया, राज्य के भीतर रहने वाले चकमाओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए राज्य बाध्य है-उन्हें जबरन बेदखल करने या बाहर निकालने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा।

नागरिकता अधिनियम, 1955 / नागरिकता नियम, 1956: धारा. 5-नियम 7,8,9,10,11,12-पंजीकरण द्वारा नागरिकता - दो दशकों से अधिक समय से अरुणाचल प्रदेश में बसे चकमाओं - उनके द्वारा आवेदन नागरिकता के लिए, किसी व्यक्ति को अभिनिर्धारित किया, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित है- कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को केवल आवेदन प्राप्त करना है और इसे केंद्रीय सरकार को भेजना है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993:

उपधारा 2 (सी), 18 (2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-अरुणाचल प्रदेश में बसे चकमा की शिकायतें स्थानीय लोगों द्वारा उत्पीड़न के कारण -आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया चकमाओं को उचित राहत देने के लिए - न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश राज्य और केंद्र सरकारों को चकमा लोगों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कहा और नागरिकता के लिए उनके आवेदनों से कानून के तहत निपटने के लिए।

बड़ी संख्या में परिवार, जिन्हें चकमा के नाम से जाना जाता है, **1964** में पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से आकर बस गए पहले असम में बस गए और फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य में आने वाले क्षेत्रों में चले गए। समय के साथ राज्य में चकमाओं के परिवार और उनकी आबादी बढ़ी बढ़कर लगभग **65,000** हो गया। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों और चकमाओं के बीच संबंध की हालत बिगड़ गई। अक्टूबर **1994** में चकमाओं के नागरिकता अधिकार समिति (सी. सी. आर. सी.) ने एक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन. एच. आर. सी.) में दायर किया, स्थानीय द्वारा चकमा की प्रताड़ना की शिकायत करते हुए। एन. एच. आर. सी. ने अरुणाचल प्रदेश राज्य और भारत संघ, प्रत्यर्थिगण **1** और **2** क्रमशः को को नोटिस जारी किए। बाद में, एनएचआरसी को यह प्रतिनिधित्व किया गया था, कि सभी अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (एएपीएसयू) ने छोड़ने का नोटिस चकमा सहित सभी कथित विदेशियों को नोटिस और धमकी दी कि यदि वे **30** सितंबर, **1995** तक राज्य नहीं छोड़ते हैं तो बल का उपयोग करेंगे। अक्टूबर **1995** में, सी. सी. आर. सी. ने लगातार दो

तत्काल याचिकाकर्ताओं को फिर से चकमाओं के जीवन पर तत्काल खतरे का आरोप लगाते हुए एन. एच. आर. सी. को भेजा। इन परिस्थितियों में, एनएचआरसी, धारा **18** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, **1993**, संविधान के अनुच्छेद **32** के तहत तत्काल याचिका दायर की गई चकमाओं को उचित राहत की मांग करता है।

केंद्र सरकार, प्रत्यर्ची नं **2** माननीय न्यायालय पहले एक शपथ पत्र इस न्यायालय में पेश किया और कहा कि वह अधिनियम की धारा **5 (1) (ए)** के अनुसार चकमाओं को नागरिकता देने के मुद्दे पर निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रतिवादी नं **1** इस संबंध में आपत्ति व्यक्त कर रहा है और प्रत्यर्ची सं. **1** के अधिकारियों ने चकमाओं द्वारा प्रस्तुत नागरिकता के लिए आवेदनों को अपने प्रत्यर्ची प्रत्यर्ची सं **2** के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया, प्रत्यर्ची सं **2** इस मुद्दे पर विचार करने से रोका गया था। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने प्रत्यर्ची नं. **1** को सिफारिश की थी चकमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सहित सभी आवश्यक कदम उठाया जाएगा। अपने जवाबी हलफनामे में प्रत्यर्ची नं. **1** ने चकमाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों का खंडन किया और कहा कि उन्होंने चकमाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस दिशा में प्रामाणिक और ईमानदार कदम उठाए अपनी क्षमता के अनुसार उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा की है। इसका प्रतिवाद प्रत्यर्ची नं. **1** की ओर से किया गया था कि खुदीराम चकमा और चकमाओं के मामले में इस न्यायालय द्वारा चकमाओं की नागरिकता का मुद्दा निर्णायक रूप से

निर्धारित किया गया था, विदेशी होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद **21** के अलावा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण के हकदार नहीं थे।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 . चकमाओं के जीवन के लिए एक स्पष्ट और आसन्न खतरा मौजूद है और चकमाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वे संविधान के अनुच्छेद **21** के संरक्षण के हकदार हैं।

लुई डी रायड्ट बनाम भारत संघ, [1991] **3** एस. सी. सी. **554** और राज्य

अरुणाचल प्रदेश बनाम खुदीराम चकमा, [1994] सपा **1** एस. सी. सी.

615 पर भरोसा किया गया।

1.2 . प्रत्यर्धी नं. **1** का पक्ष है कि उसने पर्याप्त कदम उठाए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि चकमाओं की सुरक्षा को बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद एक वर्ष से अधिक समय तक वर्तमान मामले को संभालते हुए, एन. एच. आर. सी. ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्धी सं. **1** ने छोड़ने के नोटिस जारी करने और आवश्यक प्रतिक्रिया न देकर मामले के निपटारे में देरी की और दूसरी ओर प्रत्यर्धी सं. **1** ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से चकमाओं की बेदखली को लागू करने की मांग की। इसके अलावा, प्रतिवादी क्रमांक के अनुसार **2**, **AAPSU** द्वारा उत्पन्न खतरा इतना गंभीर था कि राज्य प्रशासन के निपटान में सीआरपीएफ की दो अतिरिक्त बटालियनों को तैनात करना आवश्यक था; सी **AAPSU** और अन्य छात्र संगठनों ने

चकमा सहित सभी विदेशियों के निष्कासन के लिए आंदोलन और दबाव जारी रखा। यह बताया गया कि **AAPSU** ने शरणार्थी शिविरों पर आर्थिक नाकेबंदी लागू करना शुरू कर दिया था, जिससे राशन, चिकित्सा और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ए चकमाओं को अन्य आवश्यक सुविधाएं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ की मृत्यु हो गई।

1.3 . राज्य प्रत्येक मानव के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है चाहे वह नागरिक हो या अन्यथा। कोई भी राज्य व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दूसरे समूह को दी जाने वाली धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है; इस तरह के हमलों से संकटग्रस्त समूह की रक्षा करना कर्तव्य है। राज्य को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और स्थानीय राजनीति से बाधित हुए बिना राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए अपने कानूनी दायित्वों का पालन करना चाहिए और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहेगा।

1.4 . उत्तरदाता नं. 1, अरुणाचल प्रदेश राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक चकमा के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी और जबरन बेदखल करने का कोई भी प्रयास, ए. ए. पी. एस. यू. जैसे संगठित समूहों द्वारा उन्हें राज्य से बाहर निकालने के उनके प्रयास का विरोध होगा , यदि आवश्यक हो तो अर्धसैनिक या पुलिस बल की सेवाओं की मांग करके; और प्रतिवादी नं 2, भारत संघ, चकमा लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक अतिरिक्त बल प्रदान करेगा।

1.5 . कानून के अनुसार के अलावा, चकमाओं को बेदखल नहीं किया जाएगा उनके घरों के लिए और घरेलू जीवन और उसमें आराम से वंचित नहीं किया जाएगा।

1.6 . एएपीएसयू और किसी भी संगठन द्वारा जारी किए गए निकलने के नोटिस और अल्टीमेटम, प्रत्येक चकमा के जीवन और स्वतंत्रता के लिए अन्य समूह जो खतरे के समान है, से पहले प्रतिवादी द्वारा कानून के साथ तदनुसार निपटा जाना चाहिए।

*अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम खुदीराम चकमा, [1994] सप्ली 1 एससीसी

615. समझाया और फ़र्क समझाया गया।

2.1 . खुदिराम चकमा के मामले के विपरीत, तत्काल मामले में चकमा, जो दो दशक पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में चले गए थे, और राज्य में पैदा हुए उनके बच्चे, संविधान के तहत नागरिकता चाहते हैं और धारा 5 (1) (क) नागरिकता अधिनियम जिसमें विचार पूरी तरह से अलग हैं। धारा 5 पंजीकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है और यह प्रावधान है कि निर्धारित प्राधिकारी, उस ओर से आवेदन प्राप्त होने पर, किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। यह प्रावधान सामान्य रूप से लागू होता है और केवल एक निश्चित वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि खुदीराम चकमा के मामले में हुआ था, जिसमें नागरिकता का मुद्दा संकीर्ण संदर्भ में उठाया गया था और धारा 6 ए (2)- नागरिकता अधिनियम, 1953

तक सीमित था। न्यायालय ने कहा कि उस मामले में चकमा अधिनियम की धारा 6-ए का लाभ नहीं उठा सकते थे का जो इसके अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के लिए असम समझौता एक विशेष प्रावधान है। इसलिए, धारा 5 को उन व्यक्तियों द्वारा लागू किया जा सकता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन पंजीकरण द्वारा नागरिकता चाहते हैं; और ऐसे व्यक्तियों के आवेदनों को 1956 के नागरिकता नियम 7 से 12 के अनुसार संसाधित किया जाना है।

2.2 . नागरिकता नियम उल्लेख करते हैं कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन उस कलेक्टर को दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक रहता है और कलेक्टर आवेदन को केंद्र सरकार को प्रेषित करेगा। नियमों के नियम 8 और 9 को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कलेक्टर को केवल आवेदन प्राप्त करना है और इसे केंद्र सरकार को भेजना है, और किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करना नियम 8 के तहत गठित प्राधिकरण में निहित है और केवल वही प्राधिकरण अधिनियम से धारा 5 के तहत किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

2.3 . यह एक स्वीकृत तथ्य है कि संबंधित उप-कलेक्टर, नागरिकता के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद एक जांच करती है और यदि रिपोर्ट प्रतिकूल है, तो वह आवेदन को आगे बढ़ाने से इनकार कर देता है। इस प्रकार वह आवेदन को अस्वीकार कर देता है और केंद्रीय सरकार को अग्रेषित नहीं करता।

उप-कलेक्टर चकमा के आवेदनों को अग्रसरित करने से इंकार कर अपने कर्तव्य में असफल हो रहे हैं तथा केन्द्र सरकार को भी अधिनियम एवं नियमावली के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक रहे हैं। इसके अलावा, चकमाओं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर विचार करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है।

2.4 . भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन अधिनियम की धारा 5 के तहत चकमा को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जो इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है और कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर द्वारा भेजा जाएगा, जो उन्हें संबंधित नियम के तहत, जांच के साथ या उसके बिना, कानून के अनुसार विचार के लिए केंद्र सरकार को प्राप्त करता है; यहां तक कि वापस किए गए आवेदनों को वापस बुलाया जाएगा या संबंधित व्यक्तियों से नए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें संसाधित किया जाएगा और केंद्र सरकार को विचार के लिए भेजा जाएगा।

2.5 . जबकि किसी भी व्यक्तिगत चकमा का आवेदन लंबित है। विचार करने पर, प्रथम प्रत्यर्थी संबंधित व्यक्ति को इस आधार पर अपने कब्जे से बेदखल या हटा नहीं देगा कि वह भारत का नागरिक नहीं है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उस संबंध में निर्णय नहीं ले लेता है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सी) संख्या 720/ 1995

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

याचिकाकर्ता के लिए एफ. एस. नरीमन, सुश्री बीना माधवन, पी. एच. पारेख, सुभाष शर्मा और गोपाल जैन।

प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए के. के. वेनुपोल एस. अत्रेया, मुकुल मुद्गल और शाहिद रिज़वी

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए डी. पी. गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल, पी. परमेस्वरन और हेमंत शर्मा

न्यायालय का निर्णय निम्न द्वारा दिया गया -

अहमदी मुख्य न्यायाधिपति.

यह जनहित याचिका, संविधान का अनुच्छेद 32, के तहत एक रिट याचिका है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (जिसे इसके बाद "एन. एच. आर. सी". कहा जाता है) द्वारा दायर किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, लगभग 65,000 चकमा/हाजोंग आदिवासियों (इसके बाद इसे "चकमा" कहा जाएगा) के अधिकारों को लागू करना चाहता है। यह आरोप लगाया जाता है कि चकमा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसे इन को कुछ अरुणाचल प्रदेश के नागरिक वर्गों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पहला प्रत्यर्थी अरुणाचल प्रदेश राज्य है और दूसरा प्रत्यर्थी भारत संघ है।

एन. एच. आर. सी. की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (सं. 10/1994) के तहत की गई है। इस अधिनियम की धारा 18, एन. एच. आर. सी. को उचित मामलों में इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देती है।

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को अब संदर्भित किया जा सकता है। बड़ी संख्या में पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के चकमा लोगों को 1964 में कप्ताई पनबिजली परियोजना द्वारा विस्थापित कर दिया गया था। उन्होंने असम और त्रिपुरा में शरण ली थी। उनमें से अधिकांश इन राज्यों में बस गए और समय के साथ भारतीय नागरिक बन गए। चूंकि बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने असम में शरण ली थी, इसलिए राज्य सरकार ने उन सभी के पुनर्वास में असमर्थता व्यक्त की थी और कुछ अन्य राज्यों से इस संबंध में सहायता का अनुरोध किया था। इसके बाद, पूर्ववर्ती नेफा प्रशासन (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी-अब अरुणाचल प्रदेश) के परामर्श से, लगभग 4,012 चकमा को नेफा के कुछ हिस्सों में बसाया गया। उन्हें स्थानीय आदिवासियों के साथ परामर्श कर कुछ जमीन भी आवंटित की गई थी। भारत सरकार ने भी 4,200 प्रति परिवार रुपये की पुनर्वास सहायता को मंजूरी दी थी। अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं की वर्तमान जनसंख्या लगभग 65,000 होने का अनुमान है।

चकमाओं को नागरिकता प्रदान करने के मुद्दे पर दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा समय-समय पर विचार किया गया था। गृह राज्य मंत्री ने कई मौकों पर इस संबंध में दूसरे प्रत्यर्थी की मंशा व्यक्त की है। चकमाओं के समूहों ने याचिकाकर्ता को प्रतिनिधित्व किया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 5 (1) (ए) 1955 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाता है) के तहत नागरिकता देने के लिए अभ्यावेदन किया है। नागरिकता अधिनियम, उनके स्थानीय उपायुक्तों के समक्ष, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाल के वर्षों में, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों और चकमाओं के बीच संबंध बिगड़ गए हैं, और

चकमाओं ने शिकायत की है कि उन्हें अरुणाचल प्रदेश राज्य से जबरन निष्कासित करने के उद्देश्य से दमनकारी उपायों के अधीन किया जा रहा है।

9 सितंबर, 1994 को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, दिल्ली द्वारा इस मुद्दे को एन. एच. आर. सी. के ध्यान में लाया गया जिसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और भारत सरकार के गृह सचिव को इस संबंध में पूछताछ करने के लिए पत्र जारी किया। 30 सितंबर, 1994 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने एक जवाब फैंक्स किया जिसमें कहा गया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और चकमाओं को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी गई थी।

15 अक्टूबर, 1994 को, चकमा नागरिकता अधिकारों के लिए समिति (जिसे इसके बाद "द सी. सी. आर. सी". कहा जाता है) ने एन. एच. आर. सी. में चकमाओं के उत्पीड़न की शिकायत करते हुए एक अभ्यावेदन दायर किया। याचिका में 26 अगस्त, 1994 को "द टेलीग्राफ" में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन (जिसे इसके बाद "एएपीएसयू" कहा जाता है) ने चकमाओं सहित सभी कथित विदेशियों को 30 सितंबर, 1995 तक राज्य से जाने के लिए "छोड़ने का नोटिस" जारी किया था। एएपीएसयू ने धमकी दी थी कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह बल प्रयोग करेगा। इस मामले को एक औपचारिक शिकायत के रूप में माना गया, एन. एच. आर. सी. द्वारा और 28 अक्टूबर, 1994 को इसने पहले और दूसरे उत्तरदाता को नोटिस जारी किए, इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट मांगते हुए।

22 नवंबर, 1994 को गृह मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को एक नोट भेजा, चकमाओं को नागरिकता देने के अपने इरादे की पुष्टि करते हुए। इसने यह भी बताया कि केंद्रीय रिजर्व बलों को एएपीएसयू की धमकी की जवाबी कार्रवाई में तैनात किया गया था और राज्य प्रशासन को चकमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। 7 दिसंबर, 1994 को एन. एच. आर. सी. ने पहले और दूसरे प्रत्यर्धिगण को चकमाओं की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। अनुस्मारक भेजने के बावजूद सितंबर, 1995 तक इस निर्देश की अनदेखी की गई। 25 सितंबर, 1995 को, पहले प्रतिवादी ने एक अंतरिम जवाब दायर किया और एक पूरक रिपोर्ट दायर करने के लिए चार सप्ताह की अवधि मांगी। हालांकि, पहले प्रत्यर्धि ने अपनी समय सीमा का पालन नहीं किया।

12 अक्टूबर, 1995 को और फिर 28 अक्टूबर, 1995 को सी. सी. आर. सी. ने तत्काल याचिकाएं एनएचआरसी को भेजी, चकमा लोगों के जीवन पर तत्काल खतरे का आरोप लगाते हुए। 29 अक्टूबर, 1995 को एन. एच. आर. सी. ने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया कि पहले प्रतिवादी के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश राज्य से चकमाओं को निष्कासित करने के उद्देश्य से ए. ए. पी. एस. यू. के साथ समन्वय में काम कर रहे थे। एन. एच. आर. सी. ने कहा कि चूंकि पहला प्रतिवादी देरी कर रहा था और चूंकि उसे इस बात पर संदेह था कि क्या उसके अपने प्रयास चकमाओं को उनके अपने निवास स्थान में बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगे, इसलिए उसने उचित राहत पाने के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने का फैसला किया था।

2 नवंबर, 1995 को इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके क्षेत्र में स्थित चकमा को किसी भी बलपूर्वक, कानून के विपरीत कार्रवाई से, अपने ही आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

दूसरे प्रतिवादी, का मुद्दे पर कथन कि अब हम भारत संघ के रुख का उल्लेख कर सकते हैं। यह इंगित किया गया है कि 1964 में भारत सरकार और एनईएफए प्रशासन के बीच व्यापक चर्चा के बाद, चकमाओं को उनके पुनर्वास के उद्देश्य से वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भेजने का निर्णय लिया गया। चकमा तीन दशकों से अधिक समय से अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, और उन्होंने घनिष्ठ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध विकसित किए हैं। इस स्तर पर उन्हें उखाड़ना अव्यावहारिक और अमानवीय दोनों होगा। हमारा ध्यान फरवरी, 1972 में नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने सभी संबंधित राज्यों को सूचित किया था कि चकमा लोगों को अधिनियम की धारा 5(1)(ए) के अनुसार नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे प्रतिवादी ने आगे कहा कि चकमाओं के बच्चे, जो 1987 में अधिनियम में संशोधन से पहले भारत में पैदा हुए थे, उनके पास नागरिकता के लिए वैध दावे होंगे। भारतीय संघ के अनुसार, प्रथम प्रतिवादी इस संबंध में आपत्ति व्यक्त कर रहा है। नागरिकता नियम, 1955 के नियम 9 के अनुसार नागरिकता प्रदान करने के लिए अपनी रिपोर्ट के साथ चकमाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को अग्रेषित न करके,

पहले प्रतिवादी के अधिकारी भारत संघ को चकमा की नागरिकता के मुद्दे पर विचार करने से रोक रहे हैं। हमें आगे सूचित किया गया है कि भारत संघ नागरिकता के मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और उसने पहले प्रतिवादी से सिफारिश की है कि वह चकमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इसके लिए संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में तैनाती के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को उपलब्ध कराया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार, चकमाओं और सभी संबंधित लोगों के बीच, राज्य के भीतर चकमा को नागरिकता देने के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बातचीत का पक्षधर है, अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों की वास्तविक शिकायतों का भी निवारण करते हुए।

याचिका के अपने जवाब में पहले प्रतिवादी ने पहले तर्क दिया है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप गलत हैं; कि इसने चकमाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रामाणिक और ईमानदार कदम उठाए हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उनके जीवन और संपत्तियों की रक्षा की है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चकमाओं की नागरिकता का मुद्दा निर्णायक रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम खुदीराम चकमा, [1994] सप 1 एस. सी. सी. 615-में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके बाद इसे "खुदीराम चाकमा का मामला" कहा जाता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि चूँकि चकमा विदेशी मूल निवासी हैं, इसलिए वे अनुच्छेद 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों के संरक्षण के हकदार नहीं हैं। ऐसा होने पर, अधिकारी, किसी भी समय, चकमाओं को जाने के लिए कह सकते हैं, यदि वे चाहें

तो। पहले प्रतिवादी के अनुसार, अपना मामला हारने के बाद इस न्यायालय में, चकमाओं ने "मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।

प्रथम प्रत्यर्थी ने भारत संघ द्वारा लिए गए रुख का प्रतिवाद दायर किया है। पहला प्रत्यर्थी इस बात से इनकार करता है कि भारत संघ ने अपनी मर्जी से सीआरपीएफ बटालियनों को भेजा था; इसके अनुसार, उन्हें सहायता के लिए पत्र दिनांकित 20.9.1994 के जवाब अनुसार भेजा गया था। इसने इस बात से भी इनकार किया है कि एएपीएसयू द्वारा प्रभावित आर्थिक नाकेबंदी के कारण कुछ चकमा मारे गए थे; इसके अनुसार, ये जान का नुकसान मलेरिया महामारी का परिणाम थे। पहला प्रतिवादी दोहराता है कि राज्य की सुई जेनरिस संवैधानिक स्थिति उसे अपने क्षेत्र के भीतर बाहरी लोगों को बसने की अनुमति देने से रोकती है, कि उसके पास सीमित संसाधन हैं और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भर है; और यह कि उसके पास चकमाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं है , पहले ही लगभग रु100 करोड़ उनके रखरखाव पर खर्च किया जा चुका है। यह भी कहा गया है कि भारत संघ ने चकमाओं के रखरखाव के लिए अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को साझा करने से इनकार कर दिया है।

नागरिकता प्रदान करने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और इसके तहत नियमों के तहत नागरिकता देने के लिए आवेदन की अग्रेषित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की जाती है। उसके अनुसार आवेदन प्राप्त करने के बाद क्षेत्र का डी. सी. आवेदक के पूर्ववृत्त की आवश्यक पूछताछ करता है और संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले को राज्य सरकार को भेजते हैं जो बदले में इसे आगे केंद्र सरकार को अग्रेषित करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच पर यदि रिपोर्ट प्रतिकूल होने पर डी. सी. इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में आवेदन, यदि कोई हो, आवश्यक जांच के बाद पहले ही निस्तारण किए जा चुके हैं। डी. सी. के सामने कोई आवेदन लंबित नहीं है।"

यह इंगित किया जा सकता है कि पहले प्रतिवादी का यह रुख प्रत्यक्ष है, सितंबर 25, 1995 के अभ्यावेदन में उसके द्वारा अपनाए गए रुख का उल्लंघन, एन. एच. आर. सी. को उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जहाँ उसने कहा था:

"नागरिकता देने का सवाल पूरी तरह से नागरिकता अधिनियम 1955 नियंत्रित होता है, केंद्रीय सरकार को नागरिकता देने का एकमात्र प्राधिकार है। राज्य सरकार के पास, इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।"

यह पहले प्रतिवादी द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान के तहत, अरुणाचल प्रदेश राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और इसकी जातीयता को ध्यान में रखते हुए, यह घोषित किया गया है कि इसे संविधान के भाग X के तहत उद्धोषित किया जाएगा। यही कारण है कि ब्रिटिश शासन के दौरान लागू कानून और विनियम आज भी लागू हैं। राज्य में बड़ी संख्या में चकमाओं की बस्ती से जातीय संतुलन बिगड़ जाएगा और इसकी संस्कृति और पहचान को नष्ट कर देगा। संविधान में बनाए गए विशेष प्रावधान यदि बाहर के लोगों द्वारा राज्य की जनजातीय आबादी को आक्रमण करने की अनुमति दी जाती है तो यह इसे समाप्त कर जाएगा। इसलिए आदिवासी, चकमा को अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए एक संभावित खतरे के रूप में मानते हैं और इसलिए, इच्छुक हैं कि चकमा राज्य में खुद को शामिल न करें। इसके अलावा, केंद्रीय सहायता के बिना राज्य के वित्तीय संसाधन, जो आम तौर पर परिपूर्ण नहीं हैं, राज्य पर भारी बोझ डालेंगे जिसे वहन करना राज्य के लिए असंभव होगा। इन परिस्थितियों में, प्रथम प्रतिवादी तर्क देता है कि राज्य पर इतनी बड़ी संख्या में चकमाओं का बोझ डालना अनुचित और असंवैधानिक है।

हम पहले प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत चकमाओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा मौजूद नहीं है। और यह कि इसने चकमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। एक साल से अधिक समय तक वर्तमान मामले को संभालने के बाद, एन. एच. आर. सी. ने एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया कि छोड़ने के नोटिसों की तामील और उनके

स्वीकृत प्रवर्तन का समर्थन प्रथम प्रत्यर्थी के अधिकारियों द्वारा किया गया प्रतीत होता है। एन. एच. आर. सी. ने आगे कहा कि एक ओर, पहले प्रतिवादी ने आवश्यक प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करके मामले के निस्तारण में देरी की थी और दूसरी ओर, अपनी एजेंसियों के माध्यम से चकमाओं को बेदखल करने की मांग की थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी समय, पहले प्रतिवादी ने एएपीएसयू की गतिविधियों की निंदा करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि, पहले प्रतिवादी के खिलाफ सबसे हानिकारक तथ्य दूसरे प्रतिवादी के जवाबी हलफनामे में पाए जाते हैं। भारत संघ के आकलन में, एएपीएसयू द्वारा उत्पन्न गहरा खतरा राज्य प्रशासन के अपवहन में सीआरपीएफ की दो अतिरिक्त बटालियनों को रखने के लिए पर्याप्त था। चाहे यह राज्य सरकार के इशारे पर किया गया था या संघ द्वारा अपने दम पर किया गया था, इसका कोई औचित्य नहीं है; यह तथ्य कि यह आवश्यक हो गया था, अपने आप में काफ़ी है। दूसरे प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि 30 अक्टूबर, 1994 की समय सीमा समाप्त होने के बाद, एएपीएसयू और अन्य आदिवासी छात्र संगठनों ने आंदोलन करना जारी रखा और चकमा सहित सभी विदेशियों के निष्कासन के लिए दबाव डाला। यह बताया गया कि एएपीएसयू ने शरणार्थी शिविरों पर आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी थी, जिससे चकमाओं को राशन, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाओं आदि की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बेशक राज्य सरकार ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन एन. एच. आर. सी. की स्वतंत्र जांच कुछ और ही दिखाती है। यह तथ्य कि चकमा दवाओं की कमी के कारण नाकाबंदी के कारण मर रहे थे, एक स्थापित तथ्य है। चकमा बस्तियों में

चिकित्सा सुविधाओं की कमी और मलेरिया और पेचिश के प्रसार के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, केंद्र सरकार ने प्रथम प्रत्यर्थी को चकमा बस्ती में आवश्यक वस्तु संबंधों की सामान्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की सलाह दी। 20 सितंबर, 1995 को एएपीएसयू ने एक बार फिर से, 31 दिसंबर, 1995 को चकमाओं को हटाने के लिए नई समय सीमा का हवाला देते हुए एक अल्टीमेटम जारी किया। यह एक और खतरा है जिसका प्रथम प्रत्यर्थी ने संकेत नहीं दिया है कि वह कैसे मुकाबला करने का प्रस्ताव रखता है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा मौजूद है चकमाओं का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। लुई डी रायड्ट बनाम भारत संघ, [1991] 3 एस. सी. सी. 554 और खुदीराम चकमा के मामले में इस अदालत ने माना कि विदेशी संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण के हकदार हैं।

प्रथम प्रत्यर्थी का तर्क कि इस न्यायालय का निर्णय खुदीराम चकमा के मामले ने चकमाओं की नागरिकता पर विचार खतम है, यह गलत समझा है। उस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थी और 56 परिवार 1964 में पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से भारत चले गए और उन्हें लेडो में सरकारी शरणार्थी शिविर में रखा गया। बाद में उन्हें मियाओ में एक अन्य शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। 1966 में, राज्य सरकार ने शरणार्थियों के लिए चकमा पुनर्वास योजना तैयार की और चकमाओं को दो गाँवों में भूमि आवंटित किया गया। हालाँकि, अपीलार्थी भटक गया और निजी बातचीत द्वारा दूसरे क्षेत्र में भूमि हासिल कर ली। राज्य ने उक्त लेन-देन की वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि उस समय लागू विनियमों के तहत उस जिले के मूल

निवासी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इसमें भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता था। क्योंकि अपीलार्थी और इस भूमि पर बसने वाले अन्य लोगों के खिलाफ शिकायतें थीं, राज्य ने 15 फरवरी, 1984 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि वे उनके लिए निर्धारित क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाएं। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जो चकमा वहां बस गए थे, वे भारत के नागरिक थे और उनसे जबरन बेदखली की मांग की गई थी, राज्य उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था और, किसी भी मामले में, आदेश मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के रूप में अवैध था। नागरिकता के सवाल पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 6-ए को लागू किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्रों से असम आए थे।

जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ से एकदम पहले और जो असम में अपने प्रवेश के बाद से असम में सामान्य रूप से निवासी थे, उन्हें 1 जनवरी, 1966 से भारत का नागरिक होना माना जाएगा। अन्य जो उस तारीख के बाद और 25 मार्च, 1971 से पहले असम आए थे और आम तौर पर तब से असम में रह रहे थे वो विदेशी पाये गए थे, वे स्वयं को पंजीकृत करें। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि अपीलार्थी और अन्य लोगों ने असम समझौते के अनुसार बनाए गए इस विशेष प्रावधान के तहत नागरिकता का दावा किया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी और अन्य उक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि वे 1964 में एक छोटी अवधि के लिए असम में रहे थे और वहाँ से उस क्षेत्र में भटक गए जो अब

अरुणाचल प्रदेश राज्य के भीतर है। अपील पर इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। अतः यह स्पष्ट है कि उस मामले में, न्यायालय को नागरिकता के दावे पर अधिनियम की धारा 6-ए की भाषा के अनुसार विचार करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, खुदिराम चकमा के मामले में, यह न्यायालय को एक ऐसे मामले का पता चला, जिसमें 57 चकमा परिवार उस आदेश को चुनौती देने की मांग कर रहे थे, जिसमें उनके द्वारा सीधे तौर पर बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन, 1873 के खंड 7 का उल्लंघन में लाई गई भूमि को खाली करने की आवश्यकता थी। नागरिकता का मुद्दा संकीर्ण संदर्भ में उठाया गया था और यह अधिनियम के 6 ए (2) अनुभाग तक सीमित था। न्यायालय ने कहा कि उस मामले में चकमा, जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी थे, अधिनियम की धारा 6 ए का लाभ नहीं उठा सकते, जो उन व्यक्तियों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान है जो असम समझौते के अंतर्गत आता है। वर्तमान मामले में, चकमा अधिनियम की धारा 5 (1) (ए) के तहत नागरिकता प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, जहां विचार पूरी तरह से अलग हैं। यह धारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करती है। यह कहता है कि निर्धारित प्राधिकारी, उस में एक आवेदन की प्राप्ति पर, इसके लिए, एक ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करें, यदि वह उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। यह प्रावधान सामान्य है और किसी विशेष समूह के लोगों के लिए सीमित नहीं है जैसा धारा 6-ए के मामले में है। अतः धारा 5 , का आवाहन उनके द्वारा किया जा सकता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन पंजीकरण द्वारा नागरिकता चाहते हैं। ऐसे आवेदन इस नागरिकता

अधिनियम, 1956 (इसके बाद इसे "नियम" कहा जाता है) के भाग 2 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। नियम 7 के तहत, इस तरह का आवेदन उस कलेक्टर को किया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है। नियम 8 अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने के अधिकार का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार गृह मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव के पद से कम का अधिकारी नहीं होगा, और इसमें ऐसा अधिकारी भी शामिल होगा जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है और नियमों के तहत आने वाले किसी भी अन्य मामले में, गृह मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम का कोई अधिकारी, और इसमें ऐसा अन्य अधिकारी भी शामिल है जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है। नियम 9 अगला कलेक्टर को प्रत्येक आवेदन को धारा 5 (1) (ए) के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जैसा भी मामला हो के माध्यम से, खंड (ए) से खंड (ई) में निर्धारित मामलों पर एक रिपोर्ट के साथ, प्रेषित करने का आदेश देता है। नियम 10 में नागरिक के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है और नियम 11 और 12 में रजिस्ट्रों के रखरखाव का प्रावधान है। ये भारत के नागरिक के रूप में व्यक्तियों के पंजीकरण के संबंध में प्रासंगिक नियम हैं।

हम यहाँ पहले जो कुछ कह चुके हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि चकमा जो 1964 में पूर्व-पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए थे, पहले असम राज्य में बस गए और फिर उन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए जो अब अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। वे पिछले समय से वहाँ लगभग ढाई दशक से बसे हुए हैं और उन्होंने उक्त राज्य में अपने परिवारों का पालन-पोषण किया है। उनके बच्चों की शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं। इस प्रकार, उनमें से एक बड़ी संख्या राज्य में ही पैदा हुई थी। अब उन्हें बलपूर्वक इसे उखाड़ने का प्रस्ताव है। एएपीएसयू उन्हें जबरन पड़ोसी राज्य में भगाने की धमकी दे रहा है जो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पड़ोसी राज्य के निवासियों ने उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। इस प्रकार वे दो ताकतों के बीच सैंडविच किए जाते हैं, प्रत्येक विपरीत दिशा में धकेलता है जो केवल उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। विनाश की संभावना का सामना करते हुए एन. एच. आर. सी. को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने उन्हें सुरक्षा प्रदान करना असंभव पाते हुए, कुछ राहतों के लिए इस न्यायालय का रुख किया।

राज्य में अपने लंबे और लंबे प्रवास के कारण, चकमा जो देश में आकर बस गए हैं और राज्य में पैदा हुए हैं, वे अधिनियम की धारा 5 के साथ पढ़े गए संविधान के तहत नागरिकता चाहते हैं। हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इस तरह के अनुरोधों को संसाधित करने में

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नियमों के भाग II में रेखांकित किया गया है। हम पहले भी प्रासंगिक नियमों का पालन कर चुके हैं। इन नियमों के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन उस कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में किया जाना चाहिए, जिसकी विधिवत पुष्टि की गई है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार, नियमों के नियम 8 के तहत नामित अधिकारी में निहित है। नियम 9 के तहत, कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम की धारा 5 (1) (ए) के तहत प्रत्येक आवेदन को केंद्र सरकार को प्रेषित करे। नियम 8 और 9 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कलेक्टर को केवल आवेदन प्राप्त करना है और इसे केंद्र सरकार को भेजना है। यह केवल नियम 8 के तहत गठित प्राधिकरण है जो किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार है। इसके बाद केवल वह प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत किए गए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर सकता है। फिर भी यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदन की प्राप्ति के बाद, डिप्टी कलेक्टर (डी. सी.) जाँच करते हैं और यदि रिपोर्ट प्रतिकूल है, तो डी. सी. आवेदन को आगे बढ़ाने से इनकार करता है; दूसरे शब्दों में, वह आवेदन को अस्वीकार कर देता है, शुरुआत पर और इसे केंद्र सरकार को अग्रेषित नहीं करता है। केंद्र सरकार की शिकायत है कि चूंकि डी. सी. आवेदन अग्रेषित नहीं करता है, वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि क्या व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करें या नहीं। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि डीसी या आवेदन प्राप्त करने वाले कलेक्टर को इसे केंद्र सरकार को अग्रेषित करने का निर्देश

दिया जाना चाहिए जिस से केंद्रीय सरकार योग्यता के आधार पर गुण-दोष पर निर्णय लेने में सक्षम हो। यह स्पष्ट है कि चकमाओं के आवेदनों को केंद्र सरकार को अग्रेषित करने से इनकार कर डीसी अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं और केंद्र सरकार को अधिनियम और नियमों के तहत अपना कर्तव्य निभाने से भी रोक रहे हैं।

हम कानून के शासन द्वारा शासित देश हैं। हमारा संविधान प्रत्येक मनुष्य पर कुछ अधिकार प्रदान करता है और नागरिकों पर कुछ अन्य अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इस प्रकार राज्य प्रत्येक मनुष्य के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है-चाहे वह नागरिक हो या अन्यथा, और यह किसी भी निकाय या व्यक्तियों के समूह, जैसे कि एएपीएसयू, को चकमाओं को राज्य छोड़ने की धमकी देने की अनुमति नहीं दे सकता है, जिसमें विफल रहने पर वे ऐसा करने के लिए मजबूर होंगे। कोई भी लायक राज्य सरकार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दूसरे समूह को इस तरह की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है; संकटग्रस्त समूह को इस तरह के हमलों से बचाना उसका कर्तव्य है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो वह अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहेगी। इस तरह की धमकी देने वालों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और अपने कानूनी दायित्वों का पालन, स्थानीय राजनीति से बाधित हुए बिना राज्य में रहने वाले चकमाओं के जीवन,

स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा, अपने आवेदनों को आगे बढ़ाने से इनकार करने से, चकमाओं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और पहले और दूसरे प्रत्यर्थी को , परमादेश के एक रिट के माध्यम से, निम्नानुसार निर्देश देते हैं:

(1) प्रथम प्रत्यर्थी, अरुणाचल प्रदेश राज्य, यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक चकमा के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी और एएपीएसयू जैसे संगठित समूहों द्वारा उन्हें राज्य से जबरन बेदखल करने या बाहर निकालने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा, यदि - अर्धसैनिक या पुलिस बल की आवश्यकता हो, इस दिशा-निर्देश को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बल आवश्यक माने जाते हैं, तो पहले प्रत्यर्थी दूसरे प्रत्यर्थी, भारत संघ से ऐसा अतिरिक्त बल प्रदान करने का अनुरोध करेगा और दूसरा प्रत्यर्थी ऐसा अतिरिक्त बल प्रदान करेगा जो चकमाओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है;

(2) कानून के अनुसार के अलावा, चकमाओं को बेदखल नहीं किया जाएगा उनके घरों से और उन्हें घरेलू जीवन और उसमें आराम से वंचित नहीं किया जाएगा।

(3) एएपीएसयू और किसी अन्य द्वारा जारी किए गए छोड़ने के नोटिस और अल्टीमेटम जो समूह प्रत्येक चकमा के जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के समान है, उससे पहले प्रतिवादी द्वारा कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए;

(4) भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन अधिनियम की धारा 5 के तहत चकमा या चकमा को इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और कलेक्टर या डीसी द्वारा भेजा जाएगा, जो उन्हें संबंधित नियमों के तहत, जांच के साथ या उसके बिना, केंद्र सरकार को कानून के अनुसार विचार के लिए भेजा जाएगा ; यहां तक कि वापस किए गए आवेदन भी वापस बुलाए जाएंगे या संबंधित व्यक्तियों से नए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें संसाधित किया जाएगा और विचार के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा;

(5) जबकि किसी भी व्यक्तिगत चकमा का आवेदन विचाराधीन है, तो प्रथम प्रत्यर्थी संबंधित व्यक्ति को इस आधार पर अपने कब्जे से बेदखल या हटा नहीं देगा कि वह भारत का नागरिक नहीं है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी उस संबंध में निर्णय नहीं ले लेता है; और

(6) प्रथम प्रतिवादी याचिकाकर्ता को इस याचिका की व्यय का भुगतान करेगा जिसे हम 10,000 रुपये में निर्धारित करते हैं, आज से छह सप्ताह के भीतर एन. एच. आर. सी., नई दिल्ली के कार्यालय में जमा करेगा।

याचिका का इस प्रकार निस्तारण किया गया।

याचिका स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अर्जिता सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।